कृपया प्रकाशनार्थ **28 दिसंबर 2010**

मत्स्य अकाल तथा डिजल रिबट वापसी का ऐलान करें : राम नाईक

मुंबई, मंगलवार : "हालहि में संपन्न 'मत्स्यगंधा महोत्सव' में कृषि मंत्री श्री. शरद पवार का वक्तव्य चिंता का विषय है. महाराष्ट्र के मछुआरों के हित के लिए स्वयं श्री. पवार ने तथा महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत कुछ करने की आवश्यकता हैं. सबसे पहले राज्य में मत्स्य अकाल का ऐलान किया जाए तथा डिजल पर फिर से पहले जैसेही रियायत (रिबट) दें," ऐसी माँग पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक तथा महाराष्ट्र भाजपा के मछुआरा प्रकोष्ठ के संयोजक श्री. राजन मेहेर ने की है.

मत्स्यगंधा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री श्री. शरद पवार ने कहा कि एक ओर गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में मत्स्य उत्पादन 6 प्रति शत बढ गया है, तो दुसरी ओर महाराष्ट्र में वह 6 प्रति शत से कम हुआ है. श्री. पवार के इस वक्तव्य की ओर ध्यान खिंचते हुए श्री. राम नाईक ने कहा, "राज्य में मत्स्य उत्पादन में कम हुआ है यह बार - बार कहने के बावजूद सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया. कम से कम अब मत्स्य अकाल घोषित कर सरकार ने मछुआरों को राहत देनी चाहीए."

श्री. राम नाईक जब पेट्रोलियम मंत्री थे तब मछुआरों को उनकी बोट के लिए लगने वाले डिजल पर रियायत प्रति लीटर 35 पैसे से रु. 1.50 तक बढायी थी. डिजल तथा पेट्रोल के बढते दाम देखते हुए यह रियायत बढाने की बार - बार माँग की गयी. किंतु कृषि मंत्री श्री. शरद पवार तथा पेट्रोलियम मंत्री श्री. मुरली देवड़ा ने उसे अनदेखा किया. बाद में रियायत रु. 3 तक बढायी मगर वह सिर्फ गरीबी रेखा के निचे के मछुआरोंको ही देने का निर्णय किया. ऐसे मछुआरों के पास लाखों रुपए की लागत की बोट होना तो संभव नही है. याने वास्तव में यह रियायत सरकार ने बंद ही कर दी. इसे फिर से शुरु करने की माँग भी श्री. राम नाईक तथा श्री. राजन मेहेर ने की हैं.

गुजरात में मछुआरों के बंदरगाहों का विकास किया गया, जिसके कारण वहाँ का मत्स्य उत्पादन बढा. किंतु पिछले पाँच सालों से लगातार माँग करने के बावजूद भी महाराष्ट्र के बंदरगाहों के विकास के बारे में न केंद्र सरकार कुछ कर रही है न राज्य सरकार. मत्स्यगंधा महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण तथा उद्योगमंत्री श्री. नारायण राणे भी उपस्थित थे. श्री. राम नाईक ने आशा जतायी की अब तो केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिल कर राज्य के सातपाटी, अर्नाळा, करंजा, देवगड, मीरकरवाडा, आगरदंडा, साखरीनाते, हरणे, आदि बंदरगाहों के विकास को प्राथमिकता देगी.

मत्स्य उत्पादन में हुई कमी को देखते हुए मछुआरों को मदद करने की जरुरत है. मछुआरी तो सागर में की जा रही खेती मानी जाती है. इसलिए इन हालात में मछुआरों को भी किसानों की तरह 4 प्रतिशत ब्याज से कर्जा देना चाहीए. साथ ही साथ बरफ बनानेवाले उद्योगों को बिजली पर मिलने वाला अनुदान 40 पैसे से रु. 1.40 तक बढाना चाहिए ऐसी माँग भी श्री. राम नाईक व श्री. राजन मेहेर ने की. मछुआरों के घरों की सुरक्षा पर जोर देते हुए श्री. नाईक ने यह भी कहा कि सीआरझेड कानून का कडा पालन हो, मगर इस विषय में मुख्यमंत्री के बयान के उपलक्ष्य में 15 दिन में नई अधिसूचना आने के बाद ही वह अलग वक्तव्य देंगे.

मत्स्यगंधा महोत्सव तो हुआ, लेकिन अब सरकार मछुआरों के हित के लिए मदद भी दे ऐसी माँग फिर एक बार अंत में श्री. राम नाईक व श्री. राजन मेहेर ने की.

(कार्यालय मंत्री)